SHRI SHAHID SIDDIQUI: What will you do and when will you do it? ...(*Interruptions*)... For the last thirty-forty years, we have been hearing this. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Next question. Question No. 367.

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी: सर मुझे भी पूछना है ...(**व्यवधान**)...

†[مولانا عبیداللہ خان اعظمی : سر، مجھے بھی پوچھنا ہے.....مداخلت.....]

श्री सभापति: नहीं, बहुत हो गया। प्रश्न संख्या 367.

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी: सर, जब भी मैं हाथ उठाता हूं, आप मुझे कभी भी मौका नहीं देते हैं।

†[مولانا عبیداللہ خان اعظمی : سر، جب بھی میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، آپ مجھے کبھی بھی موقع نہیں دیتے ہیں۔]

श्री सभापति: अभी नहीं। प्रश्न संख्या 367.

Domestic violence

*367. MS. PRAMILA BOHIDAR: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there has been considerable increase in domestic violence against women during 2004-05;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the measures Government are taking to check this trend; and

(d) the number of cases registered during the year and the number of persons prosecuted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

---

†[ ] Transliteration in Urdu Script.

Statement

(a) The National Crime Records Bureau (NCRB), New Delhi under the Ministry of Home Affairs has informed that at an all India level, 50703 cases of cruelty by husband and his relatives were reported during 2003 which rose to 55439 during 2004 thereby registering an increase of 9.3% in 2004 over 2003.

(b) As per the Report dated October, 2000 of the National Family Health Survey (NFHS-2) 1998-99, the reasons which found acceptance by and large among the respondent women for a husband beating his wife included: husband suspecting wife of being unfaithful, her natal family not giving expected money or other items, wife showing disrespect for in-laws, wife going out without telling husband, wife neglecting house or children and wife not cooking food properly.

(c) The Government have taken the following measures to check increase of domestic violence against women:—

- The government has approved for introduction in parliament a legislation to protect women from domestic violence.
- Setting up of family couselling centres for couseling families in such situations.
- Setting up of helplines for women in distress.
- Support services to victims of violence through schemes such as short stay Homes and swadhar under which shelter, maintenance, couseling, capacity building, occupational training, medical aid and other services are provided.
- Redressal of grievances through interventions of National and State Commissions for Women.
- Organizing legal Literacy and Legal Awareness Camps.
- Implementation of schemes for (i) awareness generation and advocacy and (ii) economic empowerment of women through the programmes of Rashtriya Mahila Kosh, Swashakti project, Swayamsidha Project, Swawlamban programme and Support to Training & Employment Programme (STEP).

- Periodic review of laws with a view to remove provisions which may be discriminatory to women and to enhance punishments for crimes against women as well as enactment of new laws.
- Sensitisation of judiciary and police and civil administration on gender issues.
- Follow up of reports of cases of atrocities against women received from various sources, including NCW, with concerned authorities in the Central and the State Governments.

'Public order' and 'police' are State subjects as per the Seventh Schedule to the Constitution of India and as such registration, investigation, detection and prevention of crime are primarily the responsibility of the State Governments. However, the Government of India has been advising the State Governments, from time to time, to give more focused attention to improving the administration of criminal justice system and to take such measures as are necessary for the prevention of crime against women and other vulnerable sections of society. The measures suggested include:

- Sensitizing of police officials charged with the responsibility of protecting the women;
- Vigorously enforce the existing legislation relating to dowry violence.
- Set up women police cells in police stations and exclusive women police stations.
- Provide institutional support to the victims of violence.
- Provide couseling to victims of rape.
- Ensure wider recruitment of women police officers.
- Train police personnel in special laws dealing with atrocities against women.
- Setting up of Fast Track Courts.
- Setting up of Family Courts.
- Appointment of Dowry Prohibition Officers and notification of Rules under the Dowry Prohibition Act, 1961 by the State Governments.

(d) The number of cases of cruelty by husband and relatives registered in 2003 and 2004 have been mentioned in the reply to part (a). In 2005 (upto March) 11563 cases were registered. 106980 persons were chargesheeted and 12558 persons were convicted in 2003 and 113367 persons were chargesheeted and 14224 persons were convicted in 2004 for the said offence.

MS. PRAMILA BOHIDAR: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is aware of the Resolution adopted by over forty Women's Organisations and leaders on 16th August, 2005 urging for an early passage of the Prevention of Domestic Violence Bill.

श्रीमती कांति सिंह: सर, माननीय सांसद महोदया ने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है, चूंकि आज पूरे देश में जिस तरह से लिंग भेद, घरेलू हिंसा, दहेज सम्बन्धी हिंसा, यौन उत्पीड़न इत्यादि विस्तृत रूप से फैले हुए हैं, इन सबका कारण यह है कि हमारा समाज आज भी महिलाओं के प्रति हीन दृष्टिकोण अपनाए हुए है। यह मात्र एक जाति, धर्म या सम्प्रदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग में फैला हुआ है। सर, यह घरेलू हिंसा मानवाधिकार हनन का एक रूप है और यह हमारे विकास में एक बहुत बड़ा बाधक भी है। इसके तहत हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2005 नामक एक विधेयक आज ही लोक सभा में इंट्रोड्यूज भी करने जा रहे हैं, जिससे कि महिलाओं के साथ जो भेद-भाव हो रहा है या घर में जो हिंसाएं हो रही हैं, उन हिंसाओं से हम उन महिलाओं को छुटकारा दिला सकें।

MS. PRAMILA BOHIDAR: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering to have a provision for strong punishments in the proposed Act, or, any other clause or provision for rehabilitation of the victims of domestic violence.

श्रीमती कांति सिंह: सर, इन्होंने जो कहा है कि क्या इस विधेयक में इस तरह के प्रावधान हैं, निश्चित तौर पर इस विधेयक में इस तरह के प्रावधान हैं। इसमें सख्त-से-सख्त प्रावधान हैं। घर में महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है, चाहे वे पुरूष हैं, पुरूष के साथ-साथ महिलाओं की जो बहन है, बेटी है, पत्नी है, इन तमाम महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है और जो घर में हर तरह की महिलाएं रहने वाली हैं, उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है। सर, इस बिल के ऊपर डिसकशन में तो यह बात आएगी ही, जिस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करके इस बिल को पास कराएंगे। मैं समझती हूं कि पूरे सदन

की भी एक राय होगी कि इस बिल को पास किया जाए, ताकि घर में रहने वाली उन तमाम महिलाओं के साथ जो भेद-भाव हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उस पर अंकुश लगाया जा सके।

श्रीमती बृंदा कारत: सर, मेरा सवाल सेक्शन 'बी' से उठता है। अभी जवाब देते वक्त मंत्री महोदया ने कहा, उन्होंने कई कारण बताए हैं कि घरेलू हिंसा क्यों बढ़ रही है? लेकिन उनके लिखित जवाब में उन्होंने एनएफएचएस-2 का जो जिक्र किया है और जो कारण बताए हैं, सर, उससे स्पष्ट है कि वह पीड़ित और मजबूरी में जो एक सर्वे में जवाब देती है, यह उससे सम्बन्धित है। घरेलू हिंसा के जो मुख्य कारण हैं, वे राष्ट्रीय महिला आयोग के या खुद सरकार के बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय डाकुमेन्ट्स हैं, जिन्होंने वे कारण बताए हैं, जिसमें पुरूष प्रधानता की एक मानसिकता है, जिसमें औरतों का दर्जा जो नीचे गिरा हुआ है, उसका एक मुख्य सवाल है, जो औरत की एक सबौर्डिनेट स्टेटस है, उससे सम्बन्धित है। मैं यह जानना चाहूंगी कि जब यह जवाब दिया गया, तो जो ये तमाम डॉकुमेन्ट्स हैं, जो उनके जवाब से वैरिएंस रखते हैं, जो अलग बातें बताते हैं, क्या उन्होंने उसका जिक्र किया है या नहीं?

श्रीमती कांति सिंह: मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देती हूं कि आज आपने इस सदन को ज्वाइन किया है। यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है, चूंकि आपने हमेशा महिलाओं से सम्बन्धित अपनी आवाज को बुलन्द किया है। मैं समझती हूं कि निश्चित तौर पर जिन बातों की ओर आपने इशारा किया है, मैंने शुरू में ही कहा है कि लिंग भेद, हिंसा और उत्पीड़न के ऊपर यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य योजना के द्वारा जो सर्वे किया गया है, यह उसके तहत है, लेकिन कारण यह भी है कि जो महिलाओं को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि उन लोगों ने अपने ऊपर एक सोच रखा था कि हमारी यही दुर्दशा है, शायद अपनी ही गलती की वजह से हम प्रताड़ित हो रहीं हैं। लेकिन वे अपनी आवाज इसलिए बुलन्द नहीं कर पाती थीं कि हम कहां जाएं, किसके पास जाएं? दूसरी बात है कि महिलाओं के ऊपर ही यह आरोप लगा दिया जाता है कि तुम्हारे ही द्वारा गलती की गई है, तुम ही गलत हो, तुम्हारा ही आचरण खराब है, तुम ही हमारी बात को नहीं मानती, तुम हमारे परिवार को खबर नहीं देती हो, तो इन सारी बातों को ध्यान में रख कर ही यह किया गया है। बृंदा जी, मैं समझती हूं कि निश्चित तौर पर इसके लिए हमारा जो बिल है, इस बिल से आप पूर्णत: सहमत होंगी, ताकि इससे हम लोगों को राहत दी जा सके।

SHRIMATI VANGA GEETHA: I would like to know from the hon. Minister as to how many States Homes and *Swadhar* Schemes have been sanctioned so far and how many victims have been accommodated. As per the latest report, funds allocated for *Swadhar*

Scheme are not being utilised for the last three years. How many projects are pending with the Ministry under *Swadhar*?

श्रीमती कांति सिंह: सर, स्वाधार स्कीम में हम उन प्रताड़ित महिलाओं को राहत देने का काम करते हैं और जिन राज्यों के बारे में जानकारी मांगी है, वह अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्या को उस की विस्तृत रिपोर्ट भेज दूंगी।

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Dues of Post Matric Scholarship Scheme

*362. SHRI DATTA MEGHE:
SHRI VASANT CHAVAN:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether a huge accumulation of dues, under 100 per cent Centrally sponsored Post Matric Scholarship Scheme for the Other Backward Classes is to be paid to the Government of Maharashtra and other States;

(b) if so, the amount thereof, due to each of the States as on 31st March 2002, 2003, 2004 and 2005; and

(c) the reasons for growing accumulation and the steps taken for regular clearance of such dues?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI SUBBULAKSHMI JAGADEESAN): (a) to (c) In the year 2001-02 a sum of Rs. 4.39 crores was released to Maharashtra Government under the scheme of Post Matric Scholarships for OBCs against their demand of Rs. 26.96 crores. Additional funds can be released only on receipt of utilization certificate from the State Government. This certificate has not been received. The State Government also did not submit any proposal for 2002-03 and 2003-04. In the year 2004-05 Maharashtra Government submitted a demand for Rs. 200 crores. The State Government was requested to furnish a revised proposal since the budget allocation for the year 2004-05 under the scheme was only